

दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल, अति विशिष्ट इलाके में महिला सांसद झपटमारी की हो गई शिकार

दिल्ली की कानून व्यवस्था पर इससे बड़ा सवालिया निशान बया होगा कि अति विशिष्ट इलाके में झपटमार एक महिला सांसद की चेन छीन कर भाग जाए। इससे अदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी किस कदर असुरक्षित माहौल में रहने पर मजबूर है। सुरक्षा चाक-चौबंद होने के तमाम दावों के बावजूद दिल्ली में जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में झपटमारी, लूटपाट और हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं उससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। यह हाल तब है जब दिल्ली में दो-दो सरकारें हैं और पुलिस सीधे केंद्र के नियंत्रण में है। ताजबूक है कि अपराधियों पर नजर रखने के लिए अत्याधिक तकनीकी संसाधन होने पर भी अपराधों पर काबू नहीं पाया जा सका है। अगर दिल्ली पुलिस में पर्यास बल की अब भी कमी है, तो इसे पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? गौरतलब है कि दिल्ली के

चाणक्यपुरी जैसे अति विशिष्ट इलाके में सोमवार की सुबह सैर के लिए निकलीं तमिलनाडु की लोकसभा सांसद आर सुधा सरें अम झपटमारी की शिकार हो गई। पोलैंड दूतावास के पास से गुजरते समय झपटमार उनसे सोने की चेन छीन कर इलाके में यह चौंका देने वाली घटना तो है ही, इससे पुलिस की कार्यशैली और उसके प्रभाव भाग गया। छीना-झपटी के क्रम में उनके गले में चोट भी आई। पुलिस की कार्यशैली और उसके प्रभाव पर भी गंभीर सवाल दिल्ली के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले

पर भी गंभीर सवाल उत्तर है। खासतौर पर ऐसे समय में, जब संसद सत्र चल रहा हो और इस दौरान दिल्ली के केंद्रीय हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था सख्त मानी जाती है। मगर इस घटना के बाद यह कहा जा सकता है कि आम आपराधिक घटनाओं के समांतर दिल्ली में बहुस्तरीय सुरक्षा इंतजारों के धेरे वाले इलाके में भी अगर माहिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो देश के बाकी हिस्सों में क्या उम्मीद की जा सकती है?

ਅਟਾਂਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਰੇ ਬੰਧੁ

सुरेश सेठ

यह रक्षासूत्र केवल बहन-भाई
के रिश्ते का प्रतीक नहीं था,
बल्कि धर्म, शक्ति और रक्षा
का सूचक था। रक्षासूत्रों का
उपयोग सामाजिक, धार्मिक
और राजनीतिक उद्देश्यों की
पूर्ति हेतु हुआ। उदाहरण के
लिए, भगवान् श्रीकृष्ण ने
द्रौपदी की रक्षा तब की जब
उसने उन्हें रक्षासूत्र बाँधा था।
भागवत पुराण में आता है कि
जब देवासुर संग्राम में इंद्र
परेशान थे, तब उनकी पत्नी
इंद्राणी ने उनके हाथ में
रक्षासूत्र बाँधा। उसी दिन
श्रावण पूर्णिमा थी, और तभी
से इस दिन को खरक्षा
बंधन का पर्व माना गया।
राजनीतिक संदर्भ में रानी
कर्णावती ने मुगल सम्राट
हुमायूं को रक्षासूत्र भेजकर
अपने राज्य की रक्षा का
अनुरोध किया था।

संपादकीय

रक्षाबंधन और सनातन संस्कृति

डॉ. शिवानी कटारा
 सनातन संस्कृति में 'रक्षा' और 'बंधन' दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं। %रक्षा% का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि भावनात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रक्षा भी है। वहीं 'बंधन' किसी को बाधित करने वाला नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और मर्यादा से जुड़ा आत्मिक सबंध है। रक्षाबंधन का मूल बहुत प्राचीन है। इसका सबसे प्रारंभिक उद्देश खेदों में - रक्षासूत्र- के रूप में मिलता है। यजुर्वेद में ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठानों के समय राजा या यजमान की कलाई में रक्षासूत्र बाँधने की परंपरा थी, जिससे उसकी रक्षा दैविक शक्तियों के द्वारा हो सके। मंत्र था- येन बद्धो बलिराजा दानवेद्रो महाबलः। तेन त्वाम् प्रतिबद्धामि रक्षे मा चल मा चला-।

यह रक्षासूत्र कवल बहन-भाई के रिश्ते का प्रतीक नहीं था, बल्कि धर्म, शक्ति और रक्षा का सूचक था। रक्षासौत्रों का उपयोग सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हुआ। उदाहरण के लिए, भगवान् श्रीकृष्ण ने द्रोपदी की रक्षा तब की जब उसने उहाँ रक्षासूत्र बाँधा था। भागवत पुराण में आता है कि जब देवासुर संघाम में इन्द्र परेशन थे, तब उनकी पती इंद्राणी ने उनके हाथ में रक्षासूत्र बाँधा। उसी दिन श्रावण पूर्णिमा थी, और तभी से इस दिन को =रक्षा बंधन= का पर्व माना गया। राजनीतिक संदर्भ में रानी कर्णावती ने मुगल सम्प्राट हुमायूँ को रक्षासूत्र भेजकर अपने राज्य की रक्षा का अनुरोध किया था।

यह एक ऐसा पर्व है जो कर्तव्योद्धा, नारी सम्मान, सामाजिक समरसता और परिवारिक एकता को प्रेरित करता है और धर्म, समाज और आत्मीयता के बीच पुल का कार्य करता है। आज जब समाज में आत्मीय रिश्ते कमजोर पड़ते जा रहे हैं, तब रक्षाबंधन हमें स्परण करता है कि रक्षा का अर्थ केवल सुखाना नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और सेह का संवाहन है।

रक्षाबंधन भारत का एक पारंपरिक पर्व है, लेकिन इसका प्रभाव और महत्व अब केवल भारत तक सीमित नहीं रह गया है। प्रवासी भारतीयों की बढ़ती संख्या के कारण यह पर्व अब सांस्कृतिक कूटनीति, वैश्विक भाईचारे और मानवीय संबंधों के प्रतीक के रूप में उभर रहा है और अब एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम बन रहा है। सांस्कृतिक संगठनों, भारतीय दूतावासों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से भी इसे

A young girl in a red and black sari is seated on the floor, smiling as she places tilak on the forehead of a boy sitting on a small white stool. The boy is wearing a blue kurta and white pants. In front of them is a red box and a gold-colored plate containing several round sweets (laddoo). The girl is holding a small silver tray with more sweets.

तेरे धूंधट में तेरा ताज

वैश्विक दबावों के बीच देश की छवि पर ही चोट करने में लगे कृष्ण विपक्षी नेता

राहुल गांधी ने भारत सरकार पर आरोप लगाने शुरू किए हैं, वह एक गहरी राजनीतिक चूक को ही आज दर्शा रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत की विदेश नीति आज पहले से कहीं अधिक रणनीतिक, स्वायत्त और बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय हुई है।

ट्रंप के आरोप और अडानी को घसीटना: राहुल गांधी ने अपने हालिया बयानों में ट्रंप द्वारा दिए गए संकेतों और अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में कथित जांच को आपस में जोड़ते हुए कहा कि :- मोदी इसलिए ट्रंप के सामने चुप हैं क्योंकि अडानी के खिलाफ मामला चल रहा है और दोनों के वित्तीय रिश्ते उजागर हो सकते हैं। यह कहना न केवल अडानी समूह के खिलाफ बिना सबूत के अंतरराष्ट्रीय मच पर आरोपों को मजबूती देना है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री की साथ पर भी सीधा प्रहार है। भारत की वैश्विक छवि, निवेशकों का विश्वास और रणनीतिक निर्णय-क्षमता इन बयानों से प्रभावित होती है। निवेशक समुदाय ऐसी अस्थिर राजनीतिक टिप्पणियों को आर्थिक जोखिम के रूप में देखता है, जिससे भारत में निवेश का माहौल प्रभावित हो सकता है। आज राहुल गांधी को लेकर आश्वर्य तो इस बात का भी होता है कि भले ही वे नेता प्रतिपक्ष हैं, किंतु उनके बयान कितने अधिक बचकाने हैं। लगभग हर साल राहुल गांधी ने कम से कम एक बयान ऐसा जरूर दिया है, जो बाद में झूठ साबित हुआ और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो वहाँ से भी उन्हें सिर्फ फटकार मिली है।

इस संदर्भ में उनके ये बयान प्रमुखता से देखे जा सकते हैं। भारत अब 'संघीय' नहीं, 'राज्यविहीन' गणराज्य है, भारत अब चीन और पाकिस्तान से दो मोर्चों पर घिर चुका है और यह प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की विफलता है।

यूक्रेन युद्ध में भारत की 'तटस्थ' नीति को लेकर गहुल का कहना रहा कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने दम पर नहीं खड़ा हो पा रहा है क्योंकि उसकी विदेश नीति अब स्वतंत्र नहीं रही। यह बयान पश्चिमी देशों के दबावों के बीच भारत की रणनीतिक स्थायतता पर गंभीर सवाल खड़े करता प्रतीत हुआ। लदन दौरे पर जब गहुल जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि भारत में अब संस्थाएं बर्बाद हो चुकी हैं, यहाँ लोकतंत्र सिर्फ दिखावे के लिए है। इसे विदेशी भूमि पर भारत की छवि को धूमिल करने वाला बयान माना गया और संसद में इस पर विरोध दर्ज किया गया। इसी तरह से आज जब यूरोपीय देश, अमेरिका इत्यादि जिस मुस्लिम ब्रदरहुड पर प्रतिबंध लगाने के लिए विचार कर रहे हैं, उस इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथी संगठन के लिए गहुल कहते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा में दम है। वे मुस्लिम ब्रदरहुड को लोकतात्क्रिया आंदोलन के रूप में स्थापित करते हुए दिखते हैं।

क्या विपक्ष आर्थिक विषयों को नहीं समझता?

यह प्रश्न हर उस भारतीय का है जो अपने देश के हर तरोंके से मजबूत स्थिरिति में देखना चाहते हैं किंतु गहुल गांधी के व्यवहार से यह स्पष्ट होता जाता है कि भारतीय विपक्ष खासकर गहुल और

अखिलेश जैसे नेता अर्थिक नीति, वैश्विक व्यापार, भू-राजनीतिक रणनीति और वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों पर एक परिपक्व दृष्टिकोण से बात नहीं करते। इनके वक्तव्यों में आंकड़ों की कमी, नीतिगत विश्लेषण का अभाव और वैश्विक संदर्भों की अनदेखी दिखती है। इनके बयान भावनात्मक हैं, तथ्यों से रहित हैं और राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों पर भारत को वैश्विक दक्षिण का नेतृत्वकर्ता, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप हब के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और जब भारत जी-20 जैसे अवसरों का लाभ उठाकर निर्णायक की भूमिका में आ रहा है; तब ऐसी टिप्पणियां जो $\frac{1}{2}$ देश खत्म हो गया, $\frac{1}{2}$ विदेश नीति खत्म हो गई, $\frac{1}{2}$ अर्थिक गुलामी, $\frac{1}{2}$ इत्यादि यही कहती है, वे देश के भीतर नकारात्मक माहौल बनाकर भारत की उभरती भूमिका को कमजोर करने में लगे हुए हैं। आज राहुल जैसे भारतीय नेताओं को यह समझ क्यों नहीं आता कि विश्व अब भारत की नीतियों को गम्भीरता से लेता है। एक सांसद या पूर्व मुख्यमंत्री का बयान अब केवल स्थानीय अखबार की हेडलाइन नहीं बनता, वह बॉल स्ट्रीट, बीजिंग, ब्ल्सेल्स और वॉशिंगटन में पढ़ा और विश्लेषित होता है। इसलिए कहना यही होगा कि देश के अंदर से आए इन जैसे बयानों के जरिए भारत की आत्मघाती छवि गढ़ना वास्तव में आज एक बड़ी भूल है, जिसे संविधानिक संस्थाओं के माध्यम से तरंत रोका जाना चाहिए।

